Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding setting up of a Committee that to look into the demand of compensation against land acquired by government.

श्री देवजी पटेल (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद । मेरे लोक सभा क्षेत्र में एक आमरण अनशन चल रहा है, मैं उस विषय पर आपके माध्यम से सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं । महोदय, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जमीन अवाप्त हो रही है । केन्द्र से रिलेटेड 16 मैटर्स थे, जिनको हमने सार्ट-आउट कर दिए हैं । नेशनल हाइवे, अंडरपास, आरओबी, सर्विस रोड वगैरह हो गए हैं, लेकिन एक विषय अटक गया है । लैंड एक्विज़िशन में यहां से श्री नरेन्द्र मोदी जी और हम सभी ने जो बिल पास किया है, उसमें बाजार मूल्य लिखा हुआ है । वहां का बाजार मूल्य प्रति हेक्टेयर 40 से 50 लाख रुपये है । लेकिन वहां पर सरकार 4 से 6 लाख रुपये ही किसानों को दे रही है, जिससे किसानों की जमीनें बर्बाद हो रही हैं और बेचारा किसान बर्बादी के आलम पर आ गया है ।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार को यहां से एक निर्देश दिया जाए, क्योंकि राजस्थान सरकार विधान सभा में भू-माफियाओं के साथ मिलीभगत करके डीएलसी रेट घटा रही है । इसके कारण किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है । यहां से एक निर्देश दिया जाए, ताकि राजस्थान सरकार एक कमेटी गठित करे और वहां के किसानों को बाजार मूल्य से रेट दिलवाए, वहां कम से कम 40 से 50 लाख रुपये का रेट चल रहा है । अगर उसके हिसाब से पैसा दिया जाएगा, तो ही किसान बच पाएगा । वहां किसान आमरण अनशन कर रहे हैं...(व्यवधान) जिससे किसान मर रहे हैं ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री दुष्यंत सिंह को श्री देवजी पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।